कार्यकारी सारांश

राजस्थान सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट, (RSTDSP), निवेश परियोजनाओं का चौथा चरण एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्तपोषित है और राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) द्वारा कार्यान्वित है, जिसे पहले राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परियोजना (आरयूआईडीपी) के नाम से जाना जाता था। आरएसटीडीएसपी लगभग 14 शहरों में पानी और अपशिष्ट जल सेवाओं में सुधार की दिशा में राजस्थान सरकार के चल रहे प्रयासों का समर्थन करेगा। RSTDSP सेक्टर, ऋण के माध्यम से 20,000-115,000 के बीच आबादी वाले माध्यमिक शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज (WSS) सेवाओं में सुधार करना चाहता है। परियोजना निम्नलिखित प्रभावों के साथ संरेखित है: (i) राजस्थान के सभी शहरी क्षेत्रों में पीने योग्य, सस्ती, विश्वसनीय, न्यायसंगत और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ पेयजल आपूर्ति तक पहुंच में सुधार होगा । (ii) शहरी आबादी, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा । राजस्थान के माध्यमिक शहरों में शहरी सेवा वितरण में सुधार होगा ।

प्रतापगढ़ टाउन सीवरेज सबप्रोजेक्ट रुडसिको–ईएपी के चरण IV के निवेश घटक के तहत डिजाइन की गई उप परियोजनाओं में से एक है। वर्तमान में कस्बे में कोई सीवरेज व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण अधिकांश परिवार सीवेज के निपटान के लिए सेप्टिक टैंकों पर निर्भर हैं। सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले अपशिष्ट और सेप्टिक टैंकों के बिना घरों से मल और सीवेज को खुली नालियों में छोड़ दिया जाता है जो अंततः शहर के बाहरी इलाके में निचले इलाकों में जमा हो जाते हैं या खुले नाले में ले जाते हैं, जो अंततः नदी में गिर जाते हैं।

संभावित प्रभावों की जांच और आकलन- एडीबी को, बैंक के संचालन के सभी पहलुओं में पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, और पर्यावरण मूल्यांकन की आवश्यकताओं को एडीबी के सुरक्षा नीति वक्तव्य (एसपीएस), 2009 में वर्णित किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अनुसार, इस उप-परियोजना को ईआईए अध्ययन या पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। सीवरेज के लिए, उप-परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन, एडीबी रैपिड एनवायरनमेंटल असेसमेंट (आरईए) चेकलिस्ट का उपयोग करके किया गया है। पूर्व-निर्माण, निर्माण और संचालन चरणों के संबंध में संभावित नकारात्मक प्रभावों की पहचान की गई थी। यह प्रारंभिक पर्यावरण परीक्षा (आईईई) प्रतापगढ़ टाउन सीवरेज उप-परियोजना के तहत प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के घटकों को संबोधित करती है।

इस उप-परियोजना का मसौदा आईईई व्यवहार्यता/प्रारंभिक डिजाइन के आधार पर एडीबी द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया था, और इस डीबीओ पैकेज की बोली और अनुबंध में शामिल किया गया था। स्कोप, स्थान आदि में किसी भी परिवर्तन सहित अंतिम उप-परियोजना डिजाइनों को दर्शाने वाला अद्यतन आईईई, और निर्माण शुरू होने से पहले एडीबी द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है। चूंकि डिजाइनों को जोन/सबजोन/घटक-वार अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसलिए आईईई को चरणों में अपडेट करने की भी योजना है ताकि उन घटकों के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके जिनके लिए डिजाइन तैयार किए गए हैं। यह इस पैकेज का पहला अद्यतन आईईई है, और सबप्रोजेक्ट घटकों के अद्यतन डिजाइन को दर्शाता है। वर्तमान में प्रस्तावित कुल 104.68 किमी में से 102.09 किमी (लगभग 97.5%) के सीवर नेटवर्क; स्वीकृत है, जबकि, शेष 2.6 किमी नेटवर्क मुख्य रूप से राजमार्ग क्रॉसिंग को IEE के अगले अपडेट में स्वीकृत और अद्यतन किया जाएगा। संशोधित और स्वीकृत आईईई, आईईई के पुराने संस्करण का स्थान लेगा और ठेकेदार पर संविदात्मक रूप से बाध्यकारी होगा।

वर्गीकरण (i) प्रारंभिक विस्तृत डिजाइन, और (ii) पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घटकों की सबसे अधिक संभावना के आधार पर प्रतापगढ़ सीवरेज उप-परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मूल्यांकन किया गया है। पर्यावरण मूल्यांकन में सीवरेज कार्यों और पानी की आपूर्ति के लिए एडीबी की आरईए चेकलिस्ट (REA Checklist) और " अशमन परिदृश्य चेकलिस्ट (No Mitigation Scenario Checklist)" का उपयोग किया गया था। प्रतापगढ़ सीवरेज उप-परियोजनाओं के पर्यावरणीय मूल्यांकन से कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव होने की

संभावना नहीं है जो अपरिवर्तनीय, विविध या अभूतपूर्व हैं। संभावित प्रभाव, ज्यादातर साइट-विशिष्ट होते हैं और उनमें से कुछ अपरिवर्तनीय होते हैं। ज्यादातर मामलों में शमन उपायों को निर्माण स्थलों पर आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सरल उपायों के साथ डिजाइन किया जा सकता है और जो कि सिविल कार्य ठेकेदारों को पता हो ।

प्रतापगढ़ सीवरेज उपपरियोजना को एसपीएस के अनुसार पर्यावरण श्रेणी बी के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि कोई महत्वपूर्ण प्रभाव परिकल्पित नहीं है। तदनुसार, यह प्रारंभिक पर्यावरण परीक्षा (आईईई) पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए शमन और निगरानी उपाय प्रदान करती है कि परियोजना के परिणामस्वरूप कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

परियोजना का दायरा- उप-परियोजना को समग्र और एकीकृत तरीके से सीवरेज बुनियादी ढांचे में अंतराल को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहर में सीवरेज व्यवस्था में सुधार करना है, इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। विवरण डिजाइन के अनुसार कार्यों का प्रमुख दायरा है:

• प्रतापगढ़ में एसबीआर प्रौद्योगिकी उपचारित बहिःस्राव पंपिंग स्टेशनों पर 7.0 एमएलडी एसटीपी का निर्माण
• देपेश्वर तालाब के पास 7. 0 एमएलडी के एक सीवेज पंपिंग स्टेशन (एसपीएस) और 0. 10 एमएलडी के एक एमडब्ल्यूपी
• लगभग 104.68 किमी सीवर संग्रह नेटवर्क जिसमें संपत्ति कक्ष तक पाइप शामिल हैं (एचडीपीई डीडब्ल्यूसी एसएन 8 - 90.00 किमी, आरसीसी पाइप एनपी 4 - 3.5 किमी, एचडीपीई पीई -100 / पीएन -6 - 9.4 किमी के साथ अपनाने वाली ट्रेंचलेस विधि), 1. 68 किमी सीवेज पंपिंग मेन (100 मिमी और 500 मिमी व्यास) और एनएच क्रॉसिंग- 0.10 किमी
• ट्रीटेड एफ्लुएंट का पुनः उपयोग - ट्रीटेड एफ्लुएंट एलिवेटेड जलाशय (टीईईआर), ट्रीटेड एफ्लुएंट स्टोरेज जलाशय (टीईएसआर) और एफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन (ईपीएस) का डिजाइन, निर्माण, निष्पादन, परीक्षण और कमीशनिंग;
• उपचारित बहिःस्राव का निपटान - नियोक्ता द्वारा पहचाने गए एसटीपी बहिःस्राव कक्ष से सीवर पाइप का डिजाइन, निर्माण, निष्पादन, परीक्षण और चालू करना;
• कीचड़ प्रबंधन और निपटान - एसटीपी से 10 किमी की दूरी के भीतर नियोक्ता या लाइन एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए निर्दिष्ट स्थानों तक फिकल स्लज का सुरक्षित निपटान।
• मैनहोल का निर्माण;
• संपत्ति के चैम्बर से संपत्ति से सीवर आउटलेट तक लगभग 10,000 घरों का सीवर कनेक्शन (वर्ष 2026 तक);
• फिकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (Faecal Sludge and Septage Management) (एफएसएसएम) के लिए 4000 लीटर और 1000 लीटर क्षमता के 2 ट्रक और;
• स्काडा, विद्युत, यांत्रिक और संबद्ध कार्यों का प्रावधान। यदि विस्तार डिजाइन के किसी भी चरण में या निर्माण के दौरान कार्यों का दायरा बदलता है तो आईईई को अपडेट किया जाएगा।
• एक उपभोक्ता संबंध और प्रबंधन केंद्र (सीआरएमसी) का निर्माण

पर्यावरण का विवरण- उप-परियोजना घटक प्रतापगढ़ शहर और उसके आसपास के इलाकों में स्थित हैं जो कई वर्षों पहले शहरी उपयोग में परिवर्तित हो गए थे और इन स्थलों पर कोई प्राकृतिक आवास नहीं बचा है। इस परियोजना के लिए निजी भूमि का कोई अनैच्छिक भूमि अधिग्रहण प्रत्याशित नहीं है। परियोजना स्थल मौजूदा रोड राइट-ऑफ-वे (आरओडब्ल्यू) और सरकारी स्वामित्व वाली भूमि में स्थित हैं। परियोजना स्थानों में या उसके आस-पास कोई संरक्षित क्षेत्र, आर्द्रभूमि, मैंग्रोव या मुहाना नहीं हैं। मिट्टी गहरी है, और पाइप बिछाने के लिए चट्टानों को काटने की आवश्यकता नहीं है। एसटीपी साइट किला रोड पर उपलब्ध खाली सरकारी जमीन

में स्थित है। एसटीपी के प्रस्तावित स्थल पर एक आम का पेड़ है और 500 मीटर के दायरे में एक जैन गौशाला (गोशाला), एक सरकारी सेक.से. गर्ल्स स्कूल है, एक मस्जिद और किला रोड की कुछ बस्तियां मौजूद हैं। प्रतापगढ़ में शुष्क गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियों के साथ अर्ध-शुष्क गर्म जलवायु का अनुभव होता है। ठंड का मौसम दिसंबर से फरवरी तक होता है और इसके बाद मार्च से जून के अंतिम सप्ताह तक गर्मियां आती हैं। परियोजना स्थलों पर कोई संरक्षित स्मारक या ऐतिहासिक या पुरातत्व महत्व के स्थान नहीं हैं। भारत के भूकंपीय ज़ोनिंग मानचित्र के अनुसार, प्रतापगढ़ ज़ोन II के अंतर्गत आता है, जो भारत में सबसे कम भूकंप जोखिम वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र को "कम क्षति जोखिम क्षेत्र" कहा जाता है।

संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और शमन उपाय- इस मसौदे में आईईई, बेहतर बुनियादी ढांचे के स्थान, डिजाइन, निर्माण और संचालन के संबंध में नकारात्मक प्रभावों की पहचान की गई थी। प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया गया जहां परियोजना की वजह से कम से कम प्रभाव हो। इनमें शामिल हैं (i) भूमि अधिग्रहण और लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता से बचने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर सुविधाओं का पता लगाना; और (ii) भूमि के अधिग्रहण को कम करने और विशेष रूप से शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आजीविका पर प्रभाव को कम करने के लिए मुख्य/पहुंच सड़कों के साथ आरओडब्ल्यू में पाइप बिछाना।

बेहतर बुनियादी ढांचे के स्थान, डिजाइन, निर्माण और संचालन के संबंध में संभावित प्रभावों की पहचान की गई। निर्माण चरण के दौरान, मुख्य रूप से अपशिष्ट मिट्टी की मध्यम मात्रा और निवासियों, व्यवसायों और यातायात की गड़बड़ी के निपटान की आवश्यकता से प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ये शहरी क्षेत्रों में निर्माण के सामान्य अस्थायी प्रभाव हैं और उनके शमन के लिए अच्छी तरह से विकसित तरीके हैं। सभी नकारात्मक प्रभावों को स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए शमन उपाय विकसित किए गए हैं। प्रतापगढ़ उप-परियोजना के लिए तैयार की गई पुनर्वास योजना अस्थायी पुनर्वास/आजीविका के मुद्दों को संबोधित करती है जो मुख्य रूप से व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों में सीवर बिछाने से उत्पन्न होती है।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का प्रस्तावित स्थल बसावटों और संवेदनशील रिसेप्टर्स से पर्याप्त दूर खाली सरकारी भूमि है। एसटीपी को नवीनतम लागू मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है। उपचारित बहिःस्राव और कीचड़ का उपयोग कृषि जैसे लाभकारी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और जिसके लिए डिजाइन चरण में उपचार के मापदंडों पर विचार किया गया है।

कार्यों का उचित समय निर्धारण (गैर-मानसून मौसम, यातायात दबाव का समय, आदि) और सर्वोत्तम निर्माण विधियों द्वारा असुविधा को कम करने जैसे उपायों को नियोजित किया जाएगा। व्यस्त सड़कों पर सीवर बिछाने के कार्यों के लिए यातायात प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी। परिचालन चरण में, बुनियादी ढांचा नियमित रखरखाव के साथ काम करेगा, जिससे पर्यावरण प्रभावित नहीं होना चाहिए। समय-समय पर सुविधाओं की मरम्मत करने की आवश्यकता होगी, लेकिन निर्माण अवधि की तुलना में पर्यावरणीय प्रभाव बहुत कम होंगे क्योंकि काम कम होगा, केवल छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। सीवर में औद्योगिक निर्वहन को रोकने के उपाय शामिल हैं, जो सीवेज उपचार संयंत्रों के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं।

सभी नकारात्मक प्रभावों को स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए शमन उपाय विकसित किए गए हैं। निर्माण के दौरान आयोजित किए जाने वाले पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम द्वारा शमन का आश्वासन दिया जाएगा। पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि सभी उपायों को लागू किया गया है और यह निर्धारित करेगा कि पर्यावरण को संरक्षित किया गया है या नहीं। इसमें ऑन- और ऑफ-साइट अवलोकन, दस्तावेजों की जांच और श्रमिकों और लाभार्थियों के साथ साक्षात्कार शामिल होंगे। सुधारात्मक कार्रवाई के लिए किसी भी आवश्यकता की सूचना एडीबी को दी जाएगी।

पर्यावरण प्रबंधन- उपयुक्त एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने के साथ-साथ स्वीकार्य स्तर तक सभी नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए शमन उपाय प्रदान करने के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) विकसित की गई है। विभिन्न डिजाइन संबंधी उपाय पहले से ही परियोजना डिजाइन में शामिल हैं। निर्माण के दौरान, ईएमपी में शमन उपाय शामिल हैं जैसे (i) निर्माण पद्धति का चयन (ii) सार्वजनिक असुविधा को कम करने के लिए सीवर कार्यों की उचित योजना बनाना; (iii) बैरिकेडिंग, धूल दमन और नियंत्रण के उपाय; (iv) सड़कों के किनारे और ढोने की गतिविधियों के लिए यातायात प्रबंधन के उपाय; (v) पहुंच सुनिश्चित करने के लिए खाइयों के ऊपर पैदल मार्ग और तख्तों का प्रावधान बाधित नहीं होगा; और (vi) निपटान मात्रा को कम करने के लिए उत्खनित सामग्रियों का यथासंभव लाभकारी उपयोग करना। ईएमपी उप-परियोजना के पर्यावरण के अनुकूल निर्माण का मार्गदर्शन करेगा। ईएमपी में ईएमपी कार्यान्वयन की प्रभावशीलता को मापने के लिए एक निगरानी कार्यक्रम शामिल है और इसमें ऑन- और ऑफ-साइट अवलोकन, दस्तावेज़ जांच, और श्रमिकों और लाभार्थियों के साथ साक्षात्कार शामिल हैं। अद्यतन ईएमपी/एसईएमपी की एक प्रति निर्माण अवधि के दौरान हर समय साइट पर रखी जाएगी। ईएमपी को साइट पर काम करने वाले सभी ठेकेदारों के लिए बाध्यकारी बनाया जाएगा और इसे संविदात्मक खंडों में शामिल किया जाएगा। इस दस्तावेज़ में निर्धारित शर्तों के साथ गैर-अनुपालन, या कोई विचलन, अनुपालन में विफलता का गठन करेगा। संचालन चरण के प्रदर्शन की निगरानी के लिए, कच्चे और उपचारित पानी की गुणवत्ता, एसटीपी (असंशोधित और उपचारित सीवेज की गुणवत्ता) की उपचार दक्षता और एसटीपी पर कीचड़ की निगरानी के लिए दीर्घकालिक सर्वेक्षण भी होंगे। इस तरह की कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार परियोजना एजेंसी के साथ शमन और निगरानी के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन योजना का हिस्सा हैं। ईएमपी की अनुमानित कार्यान्वयन लागत 1,87,17,685 रुपये (शब्दों में एक करोड़ सत्यासी लाख सत्रह हजार छह सौ पिच्यासी रुपये) है ।

इस दस्तावेज़ में निर्धारित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ड्राफ्ट आईईई और ईएमपी को बोली और अनुबंध दस्तावेजों में शामिल किया गया है। ठेकेदार को समीक्षा और अनुमोदन के लिए एक अद्यतन ईएमपी / साइट पर्यावरण प्रबंधन योजना (एसईएमपी) प्रस्तुत करने के लिए पीआईयू को प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें (i) निर्माण कार्य शिविरों के लिए प्रस्तावित स्थल / स्थान, भंडारण क्षेत्र, सड़कें, निर्धारित क्षेत्र, निपटान क्षेत्र शामिल हैं। ठोस और खतरनाक कचरे के लिए; (ii) अनुमोदित ईएमपी के बाद विशिष्ट शमन उपाय; और (iii) ईएमपी के अनुसार निगरानी कार्यक्रम। एसईएमपी की मंजूरी से पहले कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता है। निर्माण अवधि के दौरान ईएमपी/अनुमोदित एसईएमपी की एक प्रति हमेशा साइट पर रखी जाएगी।

कार्यान्वयन व्यवस्था- राजस्थान सरकार का स्थानीय स्वशासन विभाग (LSGD) RUDSICO के माध्यम से कार्य कर रहा है, जो परियोजना निष्पादन एजेंसी है। पीएमयू को बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए रुडसिको के डिवीजन में रखा गया है। जयपुर और जोधपुर में दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और प्रत्येक परियोजना शहर/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) में पीआईयू हैं। पीएमयू एडीबी को पर्यावरण मूल्यांकन और निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने, सुरक्षा उपायों के अनुपालन की निगरानी, सुरक्षा उपायों के मुद्दों को संबोधित करने, पीआईयू को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। पीआईयू ईएमपी कार्यान्वयन, सूचना प्रकटीकरण, परामर्श और अन्य क्षेत्र-स्तरीय गतिविधियों की दिन-प्रतिदिन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। पीएमयू ने पर्यावरण के लिए एक परियोजना अधिकारी नियुक्त किया है और प्रत्येक पीआईयू ने एक सुरक्षा और सुरक्षा अधिकारी (एसएसओ) की प्रतिनियुक्ति की है। पीएमयू पर्यावरण परियोजना अधिकारी को परियोजना प्रबंधन और क्षमता निर्माण सलाहकार (पीएमसीबीसी) और निर्माण प्रबंधन और पर्यवेक्षण सलाहकार (सीएमएससी) के विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

परामर्श, प्रकटीकरण और शिकायत निवारण। हितधारकों को साइट पर चर्चा और शहर स्तर पर एक सार्वजनिक परामर्श कार्यशाला के माध्यम से आईईई विकसित करने में शामिल किया गया था, जिसके बाद व्यक्त किए गए

विचारों को आईईई और परियोजना की योजना और विकास में शामिल किया गया था। साइट पर सार्वजनिक परामर्श के अलावा, शहर स्तरीय समिति (सीएलसी) की एक हितधारक बैठक आयोजित की गई और सीएलसी ने उप-परियोजना की सराहना की और उसे मंजूरी दी। IEE को सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा, IEE के मसौदे (Draft) और पहले अद्यतन (first updated) किए गए IEE का खुलासा किया गया था, और इस अद्यतन IEE (updated IEE) को ADB और RUDSICO वेबसाइटों के माध्यम से व्यापक दर्शकों के लिए भी प्रकट किया जाएगा। परियोजना कार्यान्वयन के दौरान परामर्श प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा और विस्तारित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हितधारक परियोजना में पूरी तरह से लगे हुए हैं और इसके विकास और कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए तत्पर है। आईईई के भीतर एक शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) का वर्णन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी सार्वजनिक शिकायत का त्वरित समाधान किया जा सके।

निगरानी और रिपोर्टिंग- निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए पीएमयू, पीआईयू और सलाहकार जिम्मेदार होंगे। निर्माण के दौरान, डीबीओ ठेकेदार द्वारा आंतरिक निगरानी के परिणाम पीआईयू को उनकी मासिक ईएमपी कार्यान्वयन रिपोर्ट में दिखाई देंगे। सीएमएससी की सहायता से पीआईयू, ठेकेदार के अनुपालन की निगरानी करेगा, एक त्रैमासिक पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट (क्यूईएमआर) तैयार करेगा और पीएमयू को प्रस्तुत करेगा। पीएमयू कार्यान्वयन और अनुपालन की देखरेख करेगा और एडीबी को अर्ध-वार्षिक पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट (एसईएमआर) प्रस्तुत करेगा। एडीबी पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर डालेगा। निगरानी रिपोर्ट को रुडसिको-ईएपी/पीएमयू वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा।

निष्कर्ष- प्रतापगढ़ के नागरिक सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। उप-परियोजना मुख्य रूप से प्रावधान सीवरेज सिस्टम के माध्यम से प्रतापगढ़ शहर की पर्यावरणीय गुणवत्ता और रहने की स्थिति में सुधार के लिए डिज़ाइन की गई है। इस उप-परियोजना से होने वाले लाभों में शामिल हैं: (i) बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेष रूप से जलजनित और संक्रामक रोगों में कमी; (ii) भूजल प्रदूषण का कम जोखिम; और, (iii) उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के कारण ताजे जल संसाधन पर निर्भरता कम करना, और (iv) उपचारित अपशिष्ट निपटान मानकों को पूरा करने के कारण जल निकायों की गुणवत्ता में सुधार।

उप-परियोजना से महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। डिजाइन, निर्माण और संचालन से जुड़े संभावित प्रभावों को उचित इंजीनियरिंग डिजाइन और अनुशंसित शमन उपायों और प्रक्रियाओं के समावेश या आवेदन के माध्यम से बिना कठिनाई के मानक स्तर तक कम किया जा सकता है। दूसरे अद्यतन आईईई के निष्कर्षों के आधार पर, कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हैं और परियोजना का वर्गीकरण "बी" श्रेणी के रूप में जारी है। उपपरियोजना भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना (2006) के अंतर्गत नहीं आती है।

सिफारिशें- आईईई रिपोर्ट के मसौदे में की गई सिफारिशों का अनुपालन निम्नलिखित है; कोई महत्वपूर्ण प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए उप-परियोजना पर लागू;

इस अद्यतन के साथ पहले से लागू अनुशंसाएँ:

- इस आईईई को बोली और अनुबंध दस्तावेजों में शामिल करें- आईईई बोली और अनुबंध दस्तावेजों का हिस्सा है
- किए जाने वाले जैव विविधता मूल्यांकन रिपोर्ट से सिफारिशों को अद्यतन और कार्यान्वित करें- किया जाना है
- विस्तृत डिजाइन के आधार पर इस आईईई को अद्यतन/संशोधित करें और/या यदि कोई अप्रत्याशित प्रभाव हो, कार्यक्षेत्र, संरेखण, या स्थान में परिवर्तन- आईईई का मसौदा अद्यतन किया जा रहा है
- सीआरएमसी और एसटीपी साइटों के लिए पेड़ काटने की अनुमति प्राप्त की जाती है
- संविदा प्रदान करने पर ठेकेदार को सुरक्षा उपायों का संचालन करना- ठेकेदार को सुरक्षा प्रदान करना किया गया है

• सुनिश्चित करें कि ठेकेदार ने काम शुरू करने से पहले योग्य ईएचएस अधिकारियों को नियुक्त किया है- अनुपालन, ठेकेदार द्वारा ईएचएस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है

• परियोजना कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरण और लोगों को किसी भी प्रभाव से बचाने के लिए पीएमयू, पीआईयू, परियोजना सलाहकार और ठेकेदारों की प्रतिबद्धता- पीएमयू, पीआईयू, परियोजना सलाहकार और ठेकेदार पर्यावरण और लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

लागू करने की सिफारिश:-

• अनुपालन किए जा रहे प्रथम स्तर के जीआरएम में उप-ठेकेदारों सहित ठेकेदारों की भागीदारी

• ईएमपी के क्रियान्वयन का कड़ाई से पर्यवेक्षण किया जा रहा है

• यथाशीघ्र सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि शर्तों/प्रावधानों को विस्तृत डिजाइन में शामिल किया गया है- अनुपालन के तहत, प्रस्तावित एसटीपी की स्थापना के लिए सहमति आरएसपीसीबी में लागू होती है,

• दस्तावेजीकरण और नियमित आधार पर रिपोर्टिंग जैसा कि आईईई में दर्शाया गया है- किया जा रहा है

• हितधारकों के साथ सतत परामर्श- किया जा रहा है

• सूचना का समय पर प्रकटीकरण और शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) की स्थापना - किया जा रहा है